

साप्ताहिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक



Web: www.nyaysakshi.com | 3

खास खबर

उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल,

अमेरिकी शहरों तक होगी पहुंच

वांशगटन, (आरएनएस)। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आइसीबीएम) का फिर से परीक्षण किया है। इस माह में इस तरह का यह दूसरा परीक्षण है। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया का यह 12 वां मिसाइल परीक्षण है। मिसाइल एक हजार किमी की दूरी तय करने के बाद जापान के समुद्र में जाकर गिरी। अमेरिका के रक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षण सुबह 10.41 बजे (न्यूयार्क समय के अनुसार) किया गया। अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है। अमेरिका के लिए भी वह खतरा है। इसका संज्ञान लिया जा रहा है। उड़ेखनीय है कि अमेरिकी संसद ने हाल ही में रूस, इरान के साथ उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए थे। माना जा रहा है कि उसके जबाब में योग्यांग ने यह परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता इतनी है कि अमेरिका को भी निशाना बनाया जा सकता है। यॉहूप ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि उत्तर कोरिया के मिसाइलों की जड में अमेरिका के लॉस एंजिल्स समेत कई दूसरे शहर भी आ सकते हैं। इससे पहले भी उत्तर कोरिया ने 4 जुलाई को पहले अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था।

लंदन में नवाज शरीफ के बच्चों की भी है विदेशी कंपनी और प्रॉपर्टी

इस्लामबाद, (आरएनएस)। पनामा सामग्री की जांच ने 15 महीने पहले खुलासा किया था कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के हाइड पार्क लंदन में नवाज के बच्चों द्वारा चार में से तीन विदेशी कंपनियों का सेटअप किया गया था। इससे पहले हजारों ऐसे दस्तावेजों के बारे में पता लगाया गया जिसे पनामैनियन लॉर्स पर्स मोसैक फोन्सेका (एमएफ) द्वारा संचालित किया जाता था और यह राजनेताओं, व्यापारियों और मशहूर हस्तियों से जुड़े अपतटीय फॉर्मों से संबंधित हैं। इन दस्तावेजों से पता चला कि उनके बीटी मरियम सफदर और बेटे हूमैन तथा हसन नवाज शरीफ ने 7 करोड़ के गण के लिए लंदन स्थित चार प्रॉपर्टी को ड्यूशू बैंक के पास पिरवी रख दिया था। इसके अलावा बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड ने दो अच्युत प्रारंभिकों की खरीद के लिए उन्हें पैसे दिये। दस्तावेजों के अनुसार, दो विदेशी कंपनियों ने नेस्कोल लिमिटेड और नेल्सन होल्डिंग्स लिमिटेड को क्रमशः 1993 और 1994 में बीबीआई में शामिल किया गया था। फरवरी 2006 में मरियम ने एकल शेरयराधारक के रूप में नेस्कोल लिमिटेड के एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। बाद में मरियम को दोनों कंपनियों के लाभकारी मालिक बना दिया गया। अक्टूबर 2008 में, ड्यूशू बैंक ने उन्हें 7 करोड़ बीबीआई तक के क्रॉस कॉन्फ्रूट्टेड गण को मंजूरी दी थी। 2012 में, वित्तीय जांच एजेंसी (एफआईए) से पूछताछ के बाद, मिनर्वा ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के खुलासे में सामने आया कि युके स्थित दो कंपनियों के लाभकारी मालिक के स्वामित्व मरियम सफदर ही थीं। एमएफ ने एफआईए को ब्लोग दिया कि जुलाई 2014 तक मरियम नेस्कोल और नेल्सन होल्डिंग्स कंपनियों की मालिक थीं। इसके बाद कंपनियों का कानूनी फर्म और एजेंट बदल दिया गया। नवाज शरीफ के छोटे बेटे हसन, की भी एक कंपनी बीबीआई: हैंगॉन प्रॉफर्टीज होल्डिंग लिमिटेड थी, जिसे फरवरी 2007 में 50,000 डॉलर की पूँजी के साथ शामिल कर लिया गया था।

रूस पर प्रतिबंध वाले विधेयक पर हस्ताक्षर

कर्णे ट्रूप: व्हाइट हाउस

वांशगटन, (आरएनएस)। राष्ट्रपति डानालॉड ट्रूप ने कांग्रेस द्वारा मंजूरी प्राप्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है जो रूस पर नये प्रतिबंध लागू करेगा। व्हाइट हाउस ने घोषणा किया कि कांग्रेस द्वारा मंजूर किये गए विधेयक पर राष्ट्रपति डानालॉड ट्रूप हस्ताक्षर करेगे। शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया कि ट्रूप विधेयक के फ़ाइनल वर्जन की समीक्षा के बाद बिल पर हस्ताक्षर करेगे। वर्ही ट्रूप ने रूस के अमेरिकी चुनावों में किसी भी तरह के दखल की बात को पूरी तरह से नकार दिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा हुकामी सैंडर्स ने बताया, 'राष्ट्रपति ट्रूप ने विधेयक के शुरुआती ड्राफ्ट को पढ़ा और कुछ मामलों पर समझौता बार्ता की।' सैंडर्स ने आगे बताया, अब उन्होंने विधेयक के फाइनल वर्जन की समीक्षा की है जो इनके समझौता चर्चा के बाद संशोधित की गयी। इसे देखने के बाद ट्रूप ने मंजूरी दे दिया है और इसपर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। इस विधेयक को रूस के विदेश मंत्री सर्गें लाव्रोव ने यूएस सचिव से कहा कि अमेरिका के साथ बड़े ग्लोबल मामलों पर बातचीत के लिए रूस तैयार है। रूस विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज के मामले में आम सहमति बनाई है। अमेरिका ने पहले ही रूसी नागरिकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। पिछले साल दिसंबर में पूर्व ग्राहपति बराक ओबामा ने 35 रूसी अधिकारियों को वापस भेजने का निर्देश दिया था। वर्ही रूस में तैनात अमेरिकी को हटाये जाने पर भी नाराजगी जताई गई। इसके साथ ही रूस ने घोषणा किया कि वह अमेरिकी राजनीयों को बाहर निकाल रहा है और संपत्ति अपने दूतावास व कंसुलेट में कर्मचारियों की संख्या कम करके 450 करना होगा, इतनी ही संख्या के लिए अमेरिकी में भी रूस दूतावास को निर्देश दिया गया है। रूस वैसे अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगा रहा है जो दो डिलोर्मैटिक सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं।

देखें व्यापम घोटाले में

देखें मनोरंजन में

» वर्ष-1 » अंक-19 »

कश्मीर में तिरंगे के डड़े को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा : महबूबा मुफ्ती

नई दिल्ली, (आरएनएस)। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने संविधान के अनुच्छेद 35 ए में बदलाव के मुद्दे को उठाते हुए चेतावनी दी कि भारत का मतलब इंदिरा गांधी है। उनका इशारा नेहरू-गांधी परिवार के प्रति संघर्ष करते हुए तो कश्मीर में तिरंगे की चिह्नों को लेकर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना सरासर गलत होगा। अगर ऐसे हो तो तिरंगे को यहां थामने वाला कोई नहीं होगा। यहां के लोग विशेष प्रकृति के हैं। वह भारत में रहते हैं, क्योंकि यही एक देश है जहां हिंदू-मुस्लिम एक साथ प्रार्थना करते हैं। यहां भगवान की मूर्ति को मुस्लिम कलाकार अपने हाथों से तराशते हैं। उनका कहना था कि विविधता के लिहाज से गलत होगा। उन्होंने कहा, 'संविधान के धारा 370 से हमें विशेष दर्जा मिला है। अनुच्छेद 35 ए सुप्रीम कोर्ट में है। और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह कहते हुए चुनौती दी गई हूँ कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को इनके बाहर निकाले जाएं। अमेरिका के अलावा अन्य देशों ने विशेष दर्जा मिला है। और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह कहते हुए चुनौती दी गई हूँ। अपर उन्हें कमजोर बना रहे हैं। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को इनके बाहर निकाले जाएं। अमेरिका के अलावा अन्य देशों ने विशेष दर्जा मिला है। और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह कहते हुए चुनौती दी गई हूँ। अपर उन्हें कमजोर बना रहे हैं। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को इनके बाहर निकाले जाएं। अमेरिका के अलावा अन्य देशों ने विशेष दर्जा मिला है। और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह कहते हुए चुनौती दी गई हूँ। अपर उन्हें कमजोर बना रहे हैं। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को इनके बाहर निकाले जाएं। अमेरिका के अलावा अन्य देशों ने विशेष दर्जा मिला है। और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह कहते हुए चुनौती दी गई हूँ। अपर उन्हें कमजोर बना रहे हैं। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को इनके बाहर निकाले जाएं। अमेरिका के अलावा अन्य देशों ने विशेष दर्जा मिला है। और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह कहते हुए चुनौती दी गई हूँ। अपर उन्हें कमजोर बना रहे हैं। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को इनके बाहर निकाले जाएं। अमेरिका के अलावा अन्य देशों ने विशेष दर्जा मिला है। और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह कहते हुए चुनौती दी गई हूँ। अपर उन्हें कमजोर बना रहे हैं। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को इनके बाहर निकाले जाएं। अमेरिका के अलावा अन्य देशों ने विशेष दर्जा मिला है। और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं य